

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरियाणा राज्य में।

क्रमांक 569 /स0क0 (4)/2016,  
दिनांक 02-06-2016

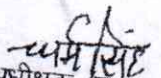
विषय:-

विभिन्न पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन का वितरण बैंकों/पोस्ट-आफिस एवं अन्य पेंशन वितरण एजेंसियों से करवाये जाने सम्बन्धी हिदायतें।

उपरोक्त विषय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, नारनौल के पत्र क्रमांक 2281 दिनांक 7-12-2015, क्रमांक 74 दिनांक 22-01-2016 के संदर्भ में।

जैसाकि आपको ज्ञात ही है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन/भत्ता योजनाओं के अन्तर्गत लाभपात्रों में पेंशन का वितरण विभिन्न बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पेंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा दिनांक 18-02-2015 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यवृत्त की प्रति भेजते हुए हिदायतें जारी की हुई है कि लाभपात्र द्वारा तीन मास में एक बार Biometric/physical (by debit vohar) के माध्यम से पेंशन प्राप्त की जानी होती है और यदि उन द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो तीन महीनों की पेंशन राशि बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पेंशन वितरण एजेंसी द्वारा विभाग को वापिस भेज दी जायेगी। लाभपात्रों द्वारा जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश यदि तीन मास में एक बार अपनी पेंशन राशि अपने खाते से नहीं निकलवाई जाती है तो उसके लिये आपको निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं:-

1. यदि लाभपात्र द्वारा तीन मास में एक बार पेंशन राशि Biometric/physical (by debit vohar) के माध्यम से खाते से नहीं निकलवाई जाती है तो वह राशि बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पेंशन वितरण एजेंसी द्वारा विभाग को वापिस भेज दी जायेगी और विभाग द्वारा भविष्य में पेंशन राशि खाते में नहीं भेजी जायेगी। लाभपात्र द्वारा जिस मास से पेंशन राशि खाते से नहीं निकलवाई जायेगी यदि उसके एक वर्ष के अन्दर-2 लाभपात्र पेंशन लेने बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर विभागीय स्तर पर प्रार्थना पत्र देकर सम्पर्क करता है तो उसकी पेंशन भविष्य में जारी कर दी जायेगी, परन्तु लाभार्थी को बकाया पेंशन राशि की अदायगी नहीं की जायेगी।
2. लाभपात्र द्वारा जिस मास से पेंशन नहीं निकलवाई गई और यदि उसके एक साल पूरा होने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर विभाग को लाभपात्र प्रार्थना पत्र देकर सम्पर्क करता है तो उसकी पेंशन जारी नहीं की जायेगी और उसका नाम विभाग की वेबसाईट से डिलीट कर दिया जायेगा और सम्बन्धित लाभपात्र अपनी नई पेंशन, नये आवेदन फार्म के साथ नियमानुसार बनवाना सुनिश्चित करेगा।

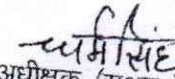
  
अधीक्षक (स0क0)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।  
/स0क0 (4)/2016, दिनांक 02-06-2016

पृ0 क्रमांक

569

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ सभी सरपंचों एवं सचिव, नगरपालिका/नगरनिगम को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें कि वह कृपया पेंशन वितरण से सम्बन्धित उक्त अनुसार लाभार्थियों को अवगत करवायें।

  
अधीक्षक (स0क0)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 10th June, 2011 ]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT**

**Notification**  
The 10th June, 2011

**No. 459-SW(4)-2011.**—In partial modification of the following eight Notifications of Haryana Government, Social Justice & Empowerment Department, the Governor of Haryana is pleased to substitute the Para relating to "Mode of Payment" as indicated against each Notification with the new provision appearing after the Table below:

Sr. No.	Notification No.	Date of Notification	Name of Scheme/ Rules	Para No. to be substituted
1.	1988-SW(4)-2006	20th September, 2006	Old Age Allowance Scheme 2005	11
2.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme Rules, 1988-89.	11
3.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Handicapped Persons Pension Scheme Rules, 1988.	11
4.	786-SW(1)-84	6th February, 1984	Haryana Dependant Children (Grant of Financial Assistance) to Destitute Children Rules, 1978.	12
5.	1803-SW(4)-2006	18th September, 2006	Ladli Social Security Allowance Scheme.	10
6.	1479-SW(4)-2007	19th October, 2007	Haryana Allowance to Eunuchs Scheme Rules, 2007.	8
7.	1322/SW(4)-2007	31st August, 2007	Haryana Allowance to Dwarf Scheme Rules, 2007.	8
8.	2351-SW(4)-2008	30th January, 2009	Financial Assistance to the Non-School Going Disabled Children Scheme.	7

**"Mode of Payment :**

- The Financial Assistance will be distributed under the Electronic Benefits Transfer (EBT) Scheme through the designated bank using biometrics authenticated smart cards.
- The Bank will not permit the beneficiary to withdraw the benefits from outside the district in which he is registered.
- In case there is no withdrawal from the bank account for a continuous period of 60 days, such bank account will be rendered "inoperative" for the purpose of this Scheme by the Bank with no further credit of benefits under this Scheme into it. Such "inoperative" bank accounts will be reported by the Bank to the Department. In case the beneficiary applies for reoperationalization of the bank account within the next 90 days with justifiable reason, the bank account may be re-operationalized with the permission of the Director. If not, the bank account will be rendered "dead" for the purpose of this Scheme and the benefits credited into the bank account after the last withdrawal would be remitted back to the Department with accrued interest by the Bank.
- If a person is detected of having more than one bank account under the EBT Scheme, all his bank accounts will be terminated. He would become ineligible to receive benefits under any Social Security Scheme of the State in future.
- Any benefits received under the Scheme by suppressing true information or making wrong claim would be recovered as arrears of land revenue with 12% interest per annum."

This issues with the approval of the Council of Ministers, Haryana, as conveyed vide U.O. No. 9/52/2011-2 Cabinet, dated 26th May, 2011.

**DHANPAT SINGH,**  
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government,  
Haryana, Social Justice & Empowerment Department.  
48750—C.S.—H.G.P., Chd.